IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

भारत में क्रिप्टो करेंसी विनियमन: वित्तीय समावेश के अवसर और चुनौतियां

डॉ. परिपूर्णानंद तिवारी

अतिथि विद्वान - वाणिज्य संकाय

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश:

यह शोध पत्र भारत में क्रिप्टोकरेंसी (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स - VDAs) के विनियमन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है तथा वित्तीय समावेश के परिप्रेक्ष्य में इसके अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करता है। फरवरी 2026 तक भारत में कोई व्यापक क्रिप्टोकरेंसी कानून नहीं बना है। सरकार आंशिक निगरानी (PMLA के तहत FIU-IND पंजीकरण) पर जोर दे रही है, जबकि 30% फ्लैट टैक्स और 1% TDS व्यवस्था बरकरार है। RBI e-रुपया (CBDC) को बढ़ावा दे रहा है। वित्तीय समावेश के लिए क्रिप्टो अंबैंकेड/अंडरबैंक्ड आबादी तक सस्ती पहुंच, रेमिटेंस और DeFi सेवाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन अस्थिरता, सुरक्षा जोखिम, नियामक अनिश्चितता और डिजिटल साक्षरता की कमी प्रमुख चुनौतियां हैं। शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है और संतुलित विनियमन की सिफारिश करता है ताकि लाभ अधिकतम हों और जोखिम न्यूनतम।

कीवर्ड्स: क्रिप्टोकरेंसी, विनियमन, वित्तीय समावेश, PMLA, FIU-IND, वर्चुअल डिजिटल एसेट, e-रुपया, ब्लॉकचेन, DeFi, अंबैंकेड आबादी।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

परिचय:

क्रिप्टोकरेंसी ने वैश्विक स्तर पर वित्तीय प्रणाली को चुनौती दी है। भारत में डिजिटल इंडिया, UPI और जन धन योजना जैसी पहलों से वित्तीय समावेश में जबरदस्त प्रगति हुई है। RBI के अनुसार, मार्च 2025 तक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स (FI-Index) 67.0 तक पहुंच गया (2024 में 64.2 से ऊपर)। विश्व बैंक ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 के अनुसार, 89% वयस्कों के पास बैंक या मोबाइल मनी अकाउंट है, लेकिन कई अकाउंट निष्क्रिय हैं और ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं तथा निम्न आय वर्ग में उपयोग की कमी बनी हुई है।इस पृष्ठभूमि में क्रिप्टोकरेंसी का अपनाव भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे ऊंचा है। Chainalysis के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत लगातार शीर्ष स्थान पर है, जहां APAC क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। भारत में क्रिप्टो अपनाव मुख्य रूप से युवा (Gen Z और Millennials), टियर-2/3 शहरों और ग्रामीण प्रवासियों द्वारा संचालित है। रिटेल और संस्थागत सेवाओं, DeFi और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर आधारित गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, जिसमें ऑन-चेन वैल्यू में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

Findings of the Financial Inclusion Index Over the Years

Financial Year	Index Value
2020-21	53.9
2021-22	56.4
2022-23	60.1
2023-24	64.2

Source: RBI

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

क्रिप्टोकरेंसी का अपनाव भारत में बहुत ऊंचा है। Chainalysis 2025 Global Crypto Adoption Index में भारत शीर्ष स्थान पर है, खासकर युवा (Gen Z और Millennials) और Tier-2/3 शहरों में। ट्रेडिंग वॉल्यूम में उतार-चढ़ाव के बावजूद अपनाव बढ़ा है। The Chainalysis 2025 Global Adoption Index विनियमन की समयरेखा: 2018 में RBI ने बैंकों पर क्रिप्टो से संबंधित सेवाएं प्रतिबंधित कीं (2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया)। 2022 में 30% टैक्स और 1% TDS लागू हुआ। मार्च 2023 से VDA सर्विस प्रोवाइडर्स (एक्सचेंज आदि) को FIU-IND के तहत PMLA रिपोर्टिंग एंटिटी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है (KYC/AML अनुपालन)। फरवरी 2026 तक कोई पूर्ण क्रिप्टो बिल पारित नहीं हुआ है; सरकार सिस्टेमिक रिस्क के कारण पूर्ण विनियमन से बच रही है और आंशिक निगरानी पर जोर दे रही है। RBI स्थिरकोइन्स (stablecoins) और निजी क्रिप्टो के जोखिमों को लेकर सतर्क है तथा e-रुपया को वैकल्पिक के रूप में आगे बढ़ा रहा है। यह शोध पत्र इन मुद्दों का विश्लेषण करता है कि क्रिप्टो विनियमन वित्तीय समावेश को कैसे प्रभावित कर सकता है।

शोध पद्धति:

यह एक गुणात्मक समीक्षा-आधारित शोध (desk research) है। प्राथमिक डेटा संग्रह नहीं किया गया; इसके बजाय द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया:

सरकारी रिपोर्ट्स: RBI Financial Inclusion Index, Financial Stability Reports, FIU-IND दिशानिर्देश।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स: World Bank Global Findex, Chainalysis Global Crypto Adoption Index।

समाचार और विश्लेषण: Reuters, The Hindu, Economic Times, Global Legal Insights (2025-26)।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

अकादमिक/अन्य स्रोत: जर्नल आर्टिकल्स और पॉलिसी पेपर्स क्रिप्टो, ब्लॉकचेन तथा वित्तीय समावेश पर। डेटा का थीमैटिक विश्लेषण किया गया — अवसर (पहुंच, लागत-कमी, नवाचार) और चुनौतियां (जोखिम, अनिश्चितता, साक्षरता) की पहचान के लिए। विश्लेषण 2025-26 की नवीनतम उपलब्ध जानकारी तक सीमित है। सीमाएं: प्राथमिक सर्वेक्षण की कमी और तेजी से बदलते नियम।

वित्तीय समावेश के अवसर:

क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय समावेश के लिए कई संभावनाएं प्रदान करती है:

अंबैंकेड/अंडरबैंक्ड तक पहुंच — बचे हुए 11% आबादी (विशेषकर ग्रामीण और महिलाओं) को मोबाइल वॉलेट के माध्यम से सेवाएं मिल सकती हैं। उच्च मोबाइल पेनेट्रेशन (900 मिलियन+ इंटरनेट यूजर्स) इसका समर्थन करता है।

कम लागत वाले रेमिटेंस — प्रवासी कामगारों के लिए सस्ते और तेज अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर (स्थिरकोइन्स के माध्यम से)। कुछ रिपोर्ट्स में 3-4% रेमिटेंस पहले से ही USDT में शिफ्ट हो चुका है।

DeFi और नवाचार — बिना पारंपरिक बैंक के उधार, बचत और निवेश के अवसर। ब्लॉकचेन भूमि रिकॉर्ड, टोकनाइजेशन आदि में पारदर्शिता ला सकता है। युवा और टियर-2/3 अपनाव — भारत में क्रिप्टो अपनाव वैश्विक शीर्ष पर है, जो युवा आबादी (18-35 वर्ष) को आर्थिक सशक्तिकरण दे सकता है।

ये अवसर डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों से मेल खाते हैं और समावेशी विकास को गति दे सकते हैं।

चुनौतियां-

नियामक अनिश्चितता — पूर्ण कानून की कमी से निवेशक और व्यवसाय प्रभावित। उच्च कर (30% + TDS) से घरेलू वॉल्यूम प्रभावित हुए और कुछ गतिविधि ऑफशोर चली गई।

अस्थिरता और जोखिम — मूल्य में उतार-चढ़ाव गरीब निवेशकों के लिए हानिकारक। कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

सुरक्षा और घोटाले — हैकिंग, फिशिंग और पोंजी स्कीम्स आम। AML/CFT जोखिम बढ़ते हैं।

डिजिटल साक्षरता और इंफ्रास्ट्रक्चर — ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और इंटरनेट/स्मार्टफोन की कमी।

सिस्टेमिक और पर्यावरणीय चिंताएं — RBI स्थिरकोइन्स को मौद्रिक स्थिरता के लिए खतरा मानता है। माइनिंग का कार्बन फुटप्रिंट भी मुद्दा।

निष्कर्ष:

भारत में क्रिप्टोकरेंसी विनियमन वित्तीय समावेश के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। अवसर महत्वपूर्ण हैं — विशेषकर अंबैंकेड आबादी, रेमिटेंस और ब्लॉकचेन नवाचार में — लेकिन चुनौतियां (अनिश्चितता, जोखिम, साक्षरता) को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को स्पष्ट, संतुलित ढांचा बनाना चाहिए जो PMLA अनुपालन को मजबूत करे, कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाए और e-रुपया को पूरक के रूप में विकसित करे। उपभोक्ता संरक्षण, शिक्षा अभियान और नवाचार को प्रोत्साहन देकर क्रिप्टो को समावेशी विकास का उपकरण बनाया जा सकता है। भविष्य में G20 जैसे मंचों पर अंतरराष्ट्रीय समन्वय भी उपयोगी होगा।

संदर्भ:

[1]. Reuters (2026). "India monitoring evolving crypto trading to ensure tax compliance."
[2]. RBI (2025). Financial Inclusion Index Report.
[3]. Chainalysis (2025). Global Crypto Adoption Index.
[4]. World Bank (2025). Global Findex Database.
[5]. Global Legal Insights (2025). Blockchain & Cryptocurrency Laws – India.
[6]. Ministry of Finance Notifications (2023-2024) on PMLA and VDA Service Providers.
[7]. Economic Times & The Hindu articles on Budget 2026 and crypto policy (2025-26).
[8]. Academic papers on cryptocurrency and financial inclusion in India (various journals, 2024-2025).